संस्थागत विकास

राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन एवं परिसर का निर्माण

- मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भवन एवं परिसर का निर्माण हेतु 117.57 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं।
- भवन निर्माण का कार्यादेश 02.11.2010 को दिया जा चुका है एवं कार्य 20.04.11 से निरन्तर प्रगति पर हैं।
- यह कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से करवाया जा रहा हैं।

राजस्थान न्यायिक अकादमी (ज्यूडिशियल एकेडेमी) की स्थापना

- राजस्थान न्यायिक अकादमी हेतु राज्य सरकार ने 14.58 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं।
- कार्यादेश 23.12.2010 को जारी किया गया। निर्माण कार्य 15.04.11 को प्रारम्भ किया गया। भवन निर्माण का कार्य प्रगतिरत हैं। इसके तहत प्रशासनिक भवन, गेस्ट हाउस, शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावास व आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।
- यह कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा करवाया जा रहा हैं।

इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (आईआईटी) की स्थापना

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जोधपुर में आईआईटी स्थापना हेतु दिनांक 11/12/09 को स्वीकृति प्रदान की गयी हैं।
- आईआईटी की स्थापना के लिए जोधपुर–नागौर रोड़ (ग्राम करवड़ झींपासनी व घड़ाव) पर 883.66 एकड़ भूमि आवंटित/अवाप्त की जा चुकी हैं।
- वर्ष 2010–11 में शैक्षणिक सत्र जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के इंजिनियरिंग कॉलेज भवन में प्रारम्भ कर दिया गया हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना

- भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा जोधपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी के क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना की जा रही है।
- इसके लिये जोधपुर–नागौर रोड़ पर ग्राम करवड़ में 20 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गयी हैं।
- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2011–12 से इस संस्थान में 140 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

फुटवियर डिजाइन एवं डवलपमेंट इन्स्टीटयूट की स्थापना

- मण्डोर–नागौर रोड़ पर ग्राम मण्डोर में निःशुल्क आवंटित 26 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर 50 करोड़ की लागत से फुटवियर डिजाइन एवं डवलपमेंट इन्स्टीट्यूट स्थापित की जा रही है। बाउण्ड्री वॉल का कार्य पूर्ण हो गया है। संस्थान में वर्कशॉप भवन, बॉयेज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल व ओडिटोरियम भवन का कार्य प्रगति पर है। संस्थान में आवासीय भवन की चारदीवारी एवं आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

- विगत तीन वर्षो में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में 292.57 लाख रूपये की लागत से स्पोटर्स कॉम्पलेक्स, कान्फ्रेन्स हॉल, एडवोकेट एकेडमी हॉल इत्यादि का निर्माण करवाया गया है।

डॉ. राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय

- विश्वविद्यालय परिसर में द्वितीय चरण में 587.00 लाख रूपये की लागत से गेस्ट हाउस, आवासीय भवन व अस्पताल का फिनिंशिग कार्य करवाया गया।
- विश्वविद्यालय विकास के तृतीय चरण में रूपये 404.32 लाख की लागत से 144 छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण व रूपये 994.00 लाख की लागत से कॉलेज भवन के निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स)

- जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अगस्त 2012 से प्रथम बैच आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इस परिसर में 7200 वर्ग मीटर में मेडिकल कॉलेज, 2600 वर्ग मीटर में नर्सिंग कॉलेज, 2800 वर्ग मीटर क्षेत्र में ऑडिटोरियम, 800 वर्ग मीटर में आयुष ब्लॉक, 600 वर्ग मीटर में डब्लू एम सी ब्लॉक तथा 200 वर्ग मीटर क्षेत्र में इलैक्ट्रिकल सबस्टेशन बन रहा है। मेडिकल कॉलेज का लगभग 60 प्रतिशत भवन निर्माण पूरा हो चुका है। आवासीय परिसर में 167 आवास बन कर पूरे हो गये है। इस परिसर में लगभग 500 वाहनों को रखने के लिये भूमिगत पार्किंग बनाये जाने की भी योजना है। साथ ही पूरे परिसर में लगभग 5 हजार पेड़ लगाये जायेंगे।

राज्य का पहला राजकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज

- बजट भाषण वर्ष 2009–10 में स्ववित्त पोषित आधार पर फिजियोथेरेपी कॉलेज संचालन की स्वीकृति दी गयी है।
- निर्माण हेतु 1 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।
- यह कॉलेज झालामण्ड स्थित सीएमएचओं कार्यालय भवन में संचालित किया जाना है व सीएमएचओ कार्यालय को राजकीय आईस फैक्ट्री भवन में स्थानान्तरित किया जाना है, जिसकी कार्यवाही जारी है।
- मेडिकल कॉलेज में राजकीय फीजियोथेरेपी कॉलेज 4.10.2010 से चालू किया जाकर 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। आईस फैक्ट्री में मरम्मत हेतु रूपये 90.23 लाख की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

स्पाईस पार्क की स्थापना

- स्पाईस बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जोधपुर में स्पाईस पार्क की स्थापना ग्राम रामपुरा भाटिया, तहसील–औसियां में 60.07 एकड़ निःशुल्क आवंटित भूमि पर की गयी है।
- 25 करोड़ रुपये की लागत से केरल की किटको कम्पनी के माध्यम से स्थापना की जा रही है, जिसमें से 22 करोड़ का कार्य हो चुका है।
- स्पाइस पार्क में मुख्यतः धनिया, जीरा, बड़ी सौंफ, मेथी जैसे बीजीय मसालों के लिए अवसंरचना व प्रसंस्करण की सुविधाएं (श्रेणीकरण, संग्रहीकरण, रंग छंटाई, पिसाई व पैकिंग इत्यादि) विकसित की गयी है।
- स्पाईस पार्क में बुनियादी संरचनाएं अंतर्राष्ट्रीय कृषकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं विकसित की गयी हैं। पार्क में बैंच प्रसंस्करण में 250 किग्रा प्रति घंटा क्षमतावाली विसंक्रमण सुविधा होगी।
- अब तक 16 मसाला निर्यातकों को 22 प्लॉट (20 एकड़ भूमि) लीज पर स्वंय के प्रसंस्करण संयत्र लगाने हेतु आवंटित किये जा चुके हैं।

माचिया बायोलॉजिकल पार्क का विकास

- पार्क विकसित किये जाने के लिए 4 करोड़ रूपये की राज्य सरकार से वित्तीय स्वीकृती (वर्ष 2010–11) प्राप्त हुई एवं कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम लि. है।
- माचिया वन क्षेत्र को भारतीय जन्तुआलय प्राधिकरण के मापदण्डों के अनुसार बायलोजिकल पार्क विकसित किये जाने के लिए 20 लाख रूपये की कन्सलटेन्सी लागत से आरएसआरडीसी के माध्यम से ले–आउट प्लान तैयार कर केन्द्रीय जन्तुआलय प्राधिकरण (सी जेड ए) से अनूमोदन प्राप्त हो गया है।
- 500 मीटर चारदीवारी एवं पानी की टंकी का कार्य पूर्ण हो गया है।
- सर्विस रोड का 1700 मीटर का कार्य हुआ है। शेष कार्य प्रगति पर है।
- चेनलिंक फेंसिंग हेतु 370 पोस्ट स्थापित किये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर है। चेनलिंक फेंसिंग का काम चालू कर दिया है। विजिटर पाथ का करीब 400 मीटर का कार्य हो गया है व शेष कार्य प्रगति पर है।

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आई.टी.बी.पी.) की वाहिनी

- गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृती अनुसार भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक वाहिनी जोधपुर, राजस्थान में स्थापित की जायेगी, ताकि आई.टी.बी.पी में तैनात कर्मियों को खासकर राजस्थान के निवासियों को सेवा के दौरान जोधपुर में परिवार के साथ रहने का मौका मिल सके। यह आंतरिक सुरक्षा व डिजास्टर मैनेजमेंट में सक्षम है। इसमें 80 एकड़ भूमि पर एक वाहिनी की स्थापना हेतु मूलभूत सुविधायें जैसे जवानों के रहने हेतु 350 पारिवारिक आवास का निर्माण होगा, केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किया जायेगा, जवानों के लिए बैरक व अस्पताल का निर्माण किया जायेगा। कैम्प में प्रशासनिक भवन व स्टोर व खेल मैदान का निर्माण किया जायेगा। आसपास के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना

- आम जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार व विज्ञान को लोकप्रिय करने के उद्धेश्य से जिले में 2.60 करोड़ की लागत से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं राज्य सरकार की 50 : 50 सहभागिता आधार पर उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इसके लिए पोलिटेक्निक कॉलेज परिसर में 4 एकड़ भूमि का आवंटन विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग को किया जा चुका है। भवन निर्माण प्लिन्थ लेवल तक हो चुका है तथा प्रथम तल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसका कार्य राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकता (एन.सी.एस.एम.) के तकनीकि मार्गदर्शन में करवाया जा रहा है।

सौर ऊर्जा पार्क

- फलौदी तहसील के ग्राम भड़ला में राज्य सरकार द्वारा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। इस सौर ऊर्जा पार्क में सोलर पावर प्लांट व सोलर संयंत्र के निर्माण में आने वाले विभिन्न पार्ट्स जैसे सोलर मोड्यूल की निर्माण इकाई भी स्थापित की जायेगी। इस पार्क में 400 केवी का ग्रिड सब–स्टेशन भी स्थापित किया जायेगा। सोलर पार्क के पहले चरण में 300 हैक्टेयर भूमि का आवंटन प्राईवेट डवलपर्स को किया जाना प्रस्तावित है। इसकी स्थापना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आरआरईसी) द्वारा की जायेगी।
- जवाहर लाल नेहरु सोलर मिशन के अन्तर्गत जोधपुर जिले में 6 कम्पनियों द्वारा 30 मेगावाट के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना कर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अन्य 10 कम्पनियों द्वारा 38 मेगावट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है जिनसे 31 जनवरी 2012 से विद्युत उत्पादन आरम्भ होना संभावित है।

जनसमस्याओं का निराकरण

मुख्यमंत्री विशेष प्रकोष्ठ

- जोधपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत 7,888 परिवादों का निस्तारण विगत 3 वर्षो में किया गया है जिनमें से 165 गरीबों को बी.पी.एल. में चयनित किया गया, 144 व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की पेंशन स्वीकृत की गयी, 84 असहाय व गरीब व्यक्तियों को नकद राशि का भुगतान किया गया व 29 लोगों को ऋण स्वीकृत करवाया गया।

सुगम एकल खिड़की

- सुगम एकल खिड़की के माध्यम से 41 सेवाओं के लिए 4,59,570 लोगों को लाभान्वित किया गया।

शिकायत निवारण पोर्टल (सुगम आर.पी.जी.)

- शिकायत निवारण पोर्टल (सुगम आर.पी.जी.) मई 2011 में प्रारंभ करने के पश्चात 807 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

सुविधाओं का विकास

पर्यटन सुविधाओं का विकास

- ग्राम खींचन व खेजड़ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रुपये 50 लाख के विकास कार्य कराये गये।
- 489 नये पर्यटक गाईडों को प्रशिक्षण दिया गया।
- घंटाघर के विकास के लिए रुपये 22.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।
- शेरगढ़ में विकास कार्य के लिए रुपये 13.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये।
- 129 लोक कलाकरों का पंजीकरण किया गया।
- 47 नये पेईंग गेस्ट आवासों का पंजीकरण किया गया।
- हर वर्ष अक्टूबर माह में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

उद्यानों का विकास

- जोधपुर शहर में मण्डोर उद्यान के विकास के लिए 131.70 लाख रूपये के कार्य स्वीकृत व उम्मेद उद्यान में विकास एवं सौन्दर्यकरण के लिए 59.27 लाख रूपये की योजना स्वीकृत।
- पंचकुण्डा की छतरियों के विकास एवं जीर्णोद्वार के लिए 1.55 करोड़ रुपये की योजना प्रस्तावित की गई है।

खेल सुविधाओं का विस्तार

- शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में 160 लाख रुपये की लागत से इण्डोर स्टेडियम का निर्माण करवाया गया।

- अमृतलाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा में विभिन्न खेल सुविधाऐं एवं पाथ–वे बनाये जाने का कार्य प्रगति पर ।
- उम्मेद राजकीय स्टेडियम में फुटबॉल अकादमी का शुभारम्भ। इसके लिए छात्रावास का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
- राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को खेल गांव के रुप में विकसित किये जाने के लिए छात्रकोष, जेडीए एवं राज्यांश लेकर शहरी जन सहभागीता योजना में 50 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत।